RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में सर्व शिक्षा अभियान के प्रदर्शन पर एक अध्ययन

[1]Sadhana Kumari and [2]Dr. Suman Sharma

[1]*Research Scholar OPJS University Churu Rajasthan*
[2]*Associate Professor OPJS University Churu Rajasthan*

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 October 2018

Keywords
शिक्षा, अधिकारिता, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत संरचना

ABSTRACT

सर्व शिक्षा अभियान एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा की गुणवत्ता प्रदान करना है। शिक्षा को सशक्तिकरण के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। यह आर्थिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से निराश गरीबों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, प्राथमिक शिक्षा के सुधार में बुनियादी सुविधाओं की सकारात्मक भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास का लक्ष्य स्कूल की उपस्थिति को बढ़ाना और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए, शुरुआत में हर जगह स्कूल प्रदान करना आवश्यक है और सभी स्कूलों को सभी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करना है। द्वारा और बड़े पैमाने पर, स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ–साथ स्कूल के भवन के विकास के लिए एक व्यापक अभ्यास है जो शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, प्रतिधारण, इक्विटी और गुणवत्ता के लक्ष्यों में योगदान करने वाले तरीकों में शामिल है।

प्रस्तावना

भारतीय शैक्षिक प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली में से एक है और यह प्राथमिक शिक्षा बनाने के लिए प्रयास इस दुनिया भर के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। शिक्षा को सशक्तिकरण के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। यह आर्थिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से निराश गरीबों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक और हर साल प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धन आवंटित किया जाता है। स्कूल शिक्षा के प्रबंधन के साथ–साथ योजना बनाना मुख्य रूप से एक राज्य का विषय रहा है, हालांकि केंद्र सरकार भी इस क्षेत्र में कानून बनाती है। इसके अलावा, शिक्षा एक ही पीढ़ी में समाजों को बदलने की शक्ति है, बच्चों को गरीबी, श्रम शोषण और बीमारी के खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करती है। मानव इतिहास की सुबह से ही शिक्षा का विकास, विविधता और विस्तार जारी है। पिछले दो दशकों में, कई विकासशील देशों ने ईएफए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रमुख पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधारों को अपनाया है, अक्सर दाता भागीदारी के साथ। विकास सहयोगी दबाव ने उन देशों को सुधारों के लिए प्रेरित किया है जो अधिक छात्र– या सीखने–केंद्रित, सक्रिय और परिणाम– या योग्यता–आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये विचार स्थानीय स्तर पर शैक्षिक, आर्थिक, प्राप्त करने के साधन के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य। हालांकि, यहां तक कि जब अच्छी तरह से योजना बनाई जाती है, तो उनका कार्यान्वयन हमेशा आशा के अनुरूप सफल नहीं रहा है, और सबूत बताते हैं कि पाठ्यक्रम सुधारों और कक्षाओं, स्कूलों और शिक्षकों की संख्या में प्राप्त वास्तविक प्रगति के अपेक्षित लक्ष्यों के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है। देशों के भीतर असमानता भी प्रकट होती है, जिससे कुछ बच्चे अक्सर धनी पृष्ठभूमि के शहरी लड़कों को सफल करते हैं, जबकि दूसरों को चुपचाप बाहर निकाल दिया जाता है, यह समझने में विफल रहता है कि कक्षा में क्या चल रहा है। शहरी और ग्रामीण बच्चों, सक्षम और अक्षम, अमीर और गरीब, लड़कों और लड़कियों के बीच सीखने में अंतराल 1990 के बाद से बढ़ा है।

भारत में प्राथमिक स्कूल शिक्षा में अवसंरचना सुविधाओं पर मूल्यांकन

प्राथमिक शिक्षा के सुधार में बुनियादी सुविधाओं की सकारात्मक भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास का लक्ष्य स्कूल की उपस्थिति को बढ़ाना और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए, शुरुआत में हर जगह स्कूल प्रदान करना आवश्यक है और सभी स्कूलों को सभी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं वाले स्कूल, जिन्हें गैर–सुसज्जित स्कूल कहा जाता है, हो सकता है कि वे ठीक से शिक्षा देने की स्थिति में न हों और ऐसे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता खराब होगी। इसके अलावा, इसने अधोसंरचना सुविधाओं के महत्व को महसूस करते हुए अध्ययन को भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों में अवसंरचनात्मक विकास को जानने का प्रयास किया है। एसएसए से पहले, प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं संतोषजनक नहीं थीं। पीने के पानी के लिए नलकूप स्कूलों

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

में उपलब्ध था। वे स्कूल जहाँ ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं और जहाँ पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, पीने के पानी के लिए पड़ोसी लोगों पर निर्भर हैं। शौचालय सुविधाओं की स्थिति भी दयनीय थी। विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग कक्षाओं की सुविधा केवल 49: स्कूलों में उपलब्ध थी। वर्गों के बीच विभाजन प्रणाली भी प्रकृति में अस्थायी थी। ब्लैक बोर्ड को छोड़कर, सभी स्कूलों में शिक्षण सामग्री जैसे ग्लोब, नक्शे उपलब्ध नहीं थे। अग्रवाल (2001) स्कूलों की कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। स्कूल के बुनियादी ढांचे के बीच एक दीवार के साथ एक स्कूल को सुरक्षित और वांछनीय माना जाता है। वर्षों से सभी राज्यों में चारदीवारी वाले स्कूलों का अनुपात बढ़ा है। असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में सीमा की दीवारों के साथ बहुत कम स्कूल हैं। सभी वर्गों के लिए डेस्क–बेंच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पुस्तकालय के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, शिक्षकों के लिए अलग कॉमन रूम उपलब्ध नहीं थे। वर्तमान अध्ययन से पता चला है कि स्कूलों की दोषपूर्ण स्थिति, उचित बाउंड्री वॉल की कमी, पेयजल सुविधा और पुस्तकालय की अनुपस्थिति, अपर्याप्त शिक्षण–शिक्षण सामग्री, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भारत में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में विकास की नकारात्मक तस्वीर पेश करती है। । अग्रवाल (2001) ने बताया कि सुविधाओं की उपलब्धता का मतलब यह नहीं है कि ऐसी सभी सुविधाएं पूरी तरह से चालू और उपयोग में हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब शौचालय, पीने के पानी की सुविधा मौजूद है लेकिन विभिन्न कारकों के कारण अनुपयोगी स्थिति में हैं। एसएसए के कार्यान्वयन के बाद शौचालयों की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। स्थायी शौचालय लगभग सभी स्कूलों में पाया गया है और शेष स्कूलों में यह निर्माणाधीन है। एसएसए ने खेल सामग्री के लिए कोई अनुदान नहीं दिया है। प्रत्येक स्कूल को कुछ अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए बहुत आवश्यक हैं। प्रत्येक स्कूल को विभिन्न प्रकार के मरम्मत कार्यों के लिए एसएसए से मरम्मत अनुदान मिलता है। यह स्कूल को ठीक से बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए, इस अध्ययन ने ै। की सकारात्मक भूमिका को बढ़ाया और भारत में स्कूलों और बुनियादी शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया।

नीति क्रियान्वयन

1. बुनियादीढांचे के खर्चों जैसे कि सिविल कार्यों के निर्माण और रखरखाव अनुदान सहित स्कूलय
2. वे आवंटन जो स्कूल में नामांकित बच्चों को सीधे लाभान्वित करते हैं, जैसे परिवहन भत्ता, वर्दी और पाठ्यपुस्तकें और स्कूली बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए मुख्यधारा की गतिविधियाँय
3. गुणवत्तारू सीखने में सुधार के लिए गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर अप्रकाशित मुद्राएं, जैसे कि जिलों में सीखने की वृद्धि कार्यक्रम और नवाचार अनुदानय
4. प्रबंधनरू प्रशासन और प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित आवंटन और
5. विविधरू सामुदायिक प्रशिक्षण और जुटाने के लिए किए गए आवंटन।
6. स्कूल के कमरों, मूत्रालयों और शौचालयों के निर्माण जैसे सिविल कार्यों को आवश्यकतानुसार लिया जाना चाहिए। धन उपलब्ध होने के बाद स्कूल भवनों के निर्माण में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
7. प्रावधान के अनुसार, निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। जिला स्तर, क्षेत्र और ग्राम स्तर पर निगरानी टीम का गठन किया जाना चाहिए। निगरानी रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस आशय का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। सभी गांवों में एसएसए के तहत अपने गांवों में नागरिक कार्यों की निगरानी के लिए ग्राम निर्माण समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
8. एसएसए का व्यापक और प्रभावी प्रचार कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाना चाहिए। माता–पिता और छात्र प्रतिनिधियों के साथ स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन। जागरूकता और सामुदायिक स्वामित्व की पीढ़ी में गैर सरकारी संगठनों की अधिक भागीदारी।
9. मिड–डे मील रजिस्टर संबंधित व्यक्ति द्वारा दैनिक आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए और टम्ब के प्रमुख ६ सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। जिला एजेंसी को स्कूलों को समय पर राशन की आपूर्ति करनी चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना के तहत धन की उचित निगरानी क्लस्टर, जोन और जिला स्तरों पर की जानी चाहिए।
10. शिक्षण के बेहतर तरीकों, बहु–ग्रेड शिक्षण, विकलांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और बच्चों को अनुशासित करने के लिए एक नियम के बजाय एक अपवाद के रूप में एक अपवाद बनाने के लिए उपयोग करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें और छात्रों की छिपी प्रतिभा को विकसित करने में सक्षम हो सकें। टीचिंग लर्निंग मटीरियल को कक्षा –ए से टप्प् के निर्धारित सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल छात्रों को पढ़ाते समय

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

किया जाना चाहिए और हेडमास्टर्स के कमरे में शोपीस के रूप में नहीं रखना चाहिए।

11. सभी विद्यालयों में कक्षा पुस्तकालयों की स्थापना की जाए और छात्रों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित किया जाए। सभी स्कूलों में खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
12. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों को मुफ्त वर्दी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास, अपने इनडोर और आउटडोर स्थानों के साथ–साथ स्कूल की इमारत को विकसित करने के लिए एक व्यापक अभ्यास है जो शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, प्रतिधारण, इक्विटी और गुणवत्ता के लक्ष्यों में योगदान देता है। चूंकि स्कूल में बच्चों के सीखने की दिशा में बुनियादी ढांचे के डिजाइन और विकास में योगदान होता है, इसलिए इसे केवल भवन निर्माण ६ मरम्मत ६ रखरखाव ६ रखरखाव के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। स्कूलों के बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से सोचने–समझने के लिए भौतिक वातावरण बनाना होगा और एकीकृत प्रणालियों के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्हें अब कमरों के संग्रह की भौतिक संरचनाओं के रूप में कल्पना नहीं की जानी चाहिए। डिजाइन को स्कूल की शैक्षिक दृष्टि के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक स्कूल के घटक और स्थान को बच्चे के अधिकार के लेंस से देखा जाना चाहिए और मौजूदा सीखने के साथ–साथ अभी भी बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल वाई। सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण की दिशा में प्रगति। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट शैक्षिक सलाहकार इंडिया लिमिटेड। नई दिल्ली ।2001 बेस्ट, जे.डब्ल्यू। और जे.वी. कहन, रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्लीरू प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा। लिमिटेड 1985।
2. भारतीय राज्यों और यूटीएस में बोसुमेटरी आर। स्कूल ड्रॉपआउटरू एक आर्थिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान पत्रिका का अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नलय 1 (4)रू 28–35।
3. सिंह एस। शिक्षा उपकररू क्या स्कूलों को फायदा हुआ है? टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई। 2005, 6. http: /epaperdaily-timesofindia-com/onसे 12 फरवरी 2015 को लिया गया।
4. सरमाह जे, दास एल.के. लर्निंग अचीवमेंट सर्वे– असम के स्मार्ट स्कूल और जनरल स्कूल पर तुलनात्मक अध्ययन। अनुसंधान और मूल्यांकन विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, असम, गुवाहाटी।
5. सरमा एन। जोरहाट जिले के विशेष संदर्भ के साथ असम के चाय–जनजातियों के शैक्षिक परिदृश्य में सुधार के एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रभाव। असम में प्राथमिक शिक्षा में अनुसंधान, एक स्थिति और प्रवृत्ति रिपोर्ट (1995– 2010), ईडीएस। जे.शर्मा, एम। पी। बोराह, एल.के. दास। अनुसंधान और मूल्यांकन विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), असम, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। Scertassam.पद। 2007
6. ठाकुरिया बी पश्चिम गुवाहाटी क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। एम। ए। शोध प्रबंध, शिक्षा विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय। 1996।
7. टॉड पीटर एलेक्स। असम कोै। से लाभ एएनआई। 2008. ूवदसपदम से लिया गया। बवउ.वद. २२ मार्च २०१४
8. थार्नडाइक। थार्नडाइक की विरासत सीखना चयन और प्रभाव का कम। व्यवहार के एनालिसिस की समाप्ति के जर्नल। 1911य 72रू 425–428।
9. पावलोव। भ्वतमेमे में एक स्पर्श उत्तेजना का सामान्यीकरण। प्रयोगात्मक ।दंसंपेपे व्यवहार के जर्नल। 1927– 1993य 59रू 521–528–1993।
10. स्किनर। छात्रों का शिक्षा व्यवहार। शिक्षा और अभिनव की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका। 1957य 02रू20।
11. बंडुरा, प्रभावी कोचिंग अभ्यास के विकास के लिए व्यवहार सीखने के सिद्धांत का महत्व। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग। 1997य 3 (1)रू 18।
12. चिशोल्म, लेयेन्डेकर। चिंतनशील फोटोग्राफी का उपयोग करते हुए सूडानी शिक्षकों के शिक्षण में परिवर्तन वोल्फेंडेन, फ्रेड और बकलर, एलिसन। चिंतनशील फोटोग्राफी का उपयोग करते हुए सूडानी शिक्षकों के शिक्षण में परिवर्तन शिक्षण और शिक्षक शिक्षा। 2008य 34रू 189–197।
13. विश्व बैंक। उप–सहारा अफ्रीका में मल्टीग्रेड शिक्षण। युगांडा, सेनेगल और गाम्बिया से सबक। वाशिंगटन डीसी, 2008।
14. डेम्बेले, लेफोका। दक्षिण अफ्रीका में पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षणरू ष्प्रतिमान बदलावष्? शैक्षिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2007य 21 (1)रू 53–60।
15. बैराट, साजिद एट अल।, अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां, शिक्षार्थी शिक्षाशास्त्र और राजनीतिक लोकतंत्ररू एक आलोचक। तुलनात्मक शिक्षा। 2007य 39 (1)रू 7–26।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved